

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- बैतूल, होशंगाबाद एवं हरदा जिले में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत हरदा-बैतूल
सेक्शन NH-47 के तहत टेमागांव से चिचोली तक मार्ग निर्माण हेतु वन मण्डल
पश्चिम बैतूल की 6.362 हेक्टेयर, होशंगाबाद (नर्मदापुरम) वन मण्डल की 4.772
हेक्टेयर एवं हरदा वन मण्डल की 0.061 हेक्टेयर कुल 11.195 हेक्टेयर वनभूमि
(ऑनलाईन आवेदित 11.399 हेक्टेयर) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हरदा
को उपयोग पर देने बाबत। (प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/153796/2022)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPR039/2023-BHO दिनांक 05.02.2024 .

-----0-----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने
विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक शर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति
पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

शर्त-A

- 1- शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान ने वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की
राशि रु0 1,21,09,413/- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 30.03.2024 को ऑनलाईन
जमा की जा चुकी है।
- 2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये
1,45,71,709/- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 30.03.2024 को जमा की जा चुकी है।
- 3- शर्त क्रमांक (3) के पालन में प्रकरण में प्राप्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि
एवं नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि क्रमशः दिनांक 30.03.2024 को एड-हॉक कैम्पा के अन्तर्गत
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।
- 4- शर्त क्रमांक (4) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत
कलेक्टर, हरदा का प्रमाण पत्र दिनांक 27.03.2024, कलेक्टर, नर्मदापुरम का प्रमाण पत्र
दिनांक 18.01.2023 एवं कलेक्टर, बैतूल का प्रमाण पत्र दिनांक 25.06.2024 प्रस्तुत किया
गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
- 5- शर्त क्रमांक (5) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

- 6- शर्त क्रमांक (6) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है कि The existing road will be dismantled keeping only 3.5 m service road and will be rehabilitated the area by preparing a site improvement plan along with avenue plantation in consultation with the forest department.
- 7- शर्त क्रमांक (7) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है, जिसका वचन पत्र संलग्न है।
- 8- शर्त क्रमांक (8) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 9- शर्त क्रमांक (9) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है कि The area of 3.58 ha. between proposed and existing alignment shall be properly fenced and planted with indigenous tree species in consultation with concerned DFO.
- 10- शर्त क्रमांक (10) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है कि Road side plantation shall be carried out.
- 11- शर्त क्रमांक (11) के पालन में आवेदक संस्था सहमत है, वचन पत्र संलग्न है।
- 12- शर्त क्रमांक (14) के पालन में ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर व्यपवर्तित वनक्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की KML file अपलोड कर दी गई है, जिसका ID No. 54097 है।
- 13- शर्त क्रमांक (13) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 14- शर्त क्रमांक (14) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन पोर्टल में अपलोड कर दिया है।
- 15- शर्त क्रमांक (15) के पालन में आवेदक संस्थान को कार्य करने की अनुमति जारी करने के उपरांत आपको पृथक से प्रेषित की जावेगी।

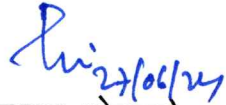
शर्त-B

- 1- शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में प्रकरण में आपके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार वृक्षारोपण का कार्य किया जावेगा।
- 3- शर्त क्रमांक (3) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा अतिरिक्त एन.पी.वी. जमा करने का वचन पत्र दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
- 4- शर्त क्रमांक (4) से (16) तक के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


भवदीय


(एच.एस. मोहन्ता)
भोपाल, दिनांक 28/06/2024

पृ. क्रमांक/एफ-5/1315/2023/10-11/3397
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), बैतूल/होशंगाबाद (नर्मदापुरम), मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, पश्चिम बैतूल/होशंगाबाद (नर्मदापुरम) एवं हरदा, मध्यप्रदेश।
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, हरदा, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई / PROJECT IMPLEMENTATION UNIT

मकान नं. 54-55 (प्रथम तल), अमरलोक कॉलोनी, हरदा (म.प्र.)-461331

H.No. 54-55 (1st Floor) Amarlok Colony Harda (M.P.)-461331

दूरभाष / Phone : +91 75773 56227 ई-मेल / E-Mail ID: piuharda@nhai.org,



NHAI/PIU Harda/NH-47/T-C/Forest/2024/4389

25th June, 2024

To,

The APCCF (Land Management) and Nodal Officer,
Govt. of Madhya Pradesh,
Block-C, Van Bhawan, Bhopal (M.P.)

Sub: Diversion of 11.195 ha (online-11.399 ha) Reserved & Protected Forest land additionally required for 4- laning of Harda-Betul Section of National Highway (NH-47) from Temagaon Km. 30+000 to Chicholi Km.81+000 (Length 51 Km) under Bharatmal Pariyojna Economic Corridor (Phase-1) in favour of Project Director, National Highway Authority of India in Betul, Hoshangabad (Narmadapuram) & Harda Districts of Madhya Pradesh (Online Proposal No. PF/MP/Road/153796/2022) - **Submission of Compliance report as per condition stipulated in stage-I clearance (In-Principal Approval) - reg.**

- Ref.:** (i) Your office letter no. 3049 dated 11.06.2024
(ii) This office letter no. 4178 dated 17.05.2024
(iii) This office letter no. 4033 dated 03.04.2024
(iv) DFO Harda letter no. 1840 dated 19.03.2024
(v) DFO Betul (West) letter no. 692 dated 07.03.2024
(vi) DFO Narmadapuram letter no. 1994 dated 26.02.2024
(vii) Regional Office, MoEF&CC Bhopal letter dated 05.02.2024

Sir,

This is in reference to this office letter dated 17.05.2024 (ref. - ii) vide which, it was requested to grant Stage-II clearance & accord Working permission to start work on the subject forest land.

2. In this regard, it is pertinent to mention that MoEF&CC vide letter dated 05.02.2024 (ref. - vii) has accorded "in-principle" approval (Stage-I clearance) for diversion of 11.195 ha. additional forest land based on the decision of Regional Empowered Committee for the forest proposal no. 153796. The point wise compliance of the conditions mentioned in aforesaid "in-principle" approval are as under:

S. No	Conditions	Remarks
A.		
1	Cost of compensatory afforestation on the 25.00 ha degraded-forest land at prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provisions for anticipated cost increase for the works scheduled for subsequent years.	The Cost of Compensatory Afforestation, cost of NPV and other amount is 2,83,73,339 paid by NEFT UTR No LMS 4090050054347 to CAMPA account no 1507661153796668 dated 30.03.2024 CAMPA Challan dated 21.03.2024 (Annex-I) and Account Statement dated 30.03.2024 is enclosed for

Amik
PP

S. No	Conditions	Remarks
2	The State Government shall charge Net Present Value (NPV) for the 11.195 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 In WP (C) No. 202/1995 and as per the (2) guidelines Issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06/01/2022 In this regard.	ready reference (Annex-II)
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	
4	Complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	Forest land is being affected in three forest divisions, viz. Harda (0.061 ha), Narmadapuram (4.772 ha) and Betul (6.362 ha). FRA certificates for Harda, Betul and Narmadapuram districts are hereby attached.
5	All conditions of CWLW/SBWL/NBWL shall be strictly complied, wherever applicable.	Agreed
6	Before surrendering the area of already approved proposal No. 5/2018 (56.515 ha) from Km 40.400 to Km 41.490 (area 1.68 ha) and Km 46.900 to Km 47.300 (1.90 ha) to the forest department, the User Agency shall dismantle the existing road keeping only 3.5 m service road and will also rehabilitate the area by preparing a site improvement plan along with avenue plantation in consultation with the forest department.	Agreed, the existing road will be dismantled keeping only 3.5 m service road and will be rehabilitated the area by preparing a site improvement plan along with avenue plantation in consultation with the forest department.
7	The existing road shall be completely removed and muck shall be disposed off outside the forest area by the User Agency at their own cost.	Agreed
8	After removal of the muck from the existing road the same shall be planted with plants of native species in consultation with the Forest Department with 10 years maintenance. If needed, good fertile soil may also be imported from outside forest areas. The cost shall be borne by the user agency.	Agreed
9	The area (3.58 ha) between the proposed alignment and existing road shall be properly fenced and planted with indigenous tree species in consultation with the DFO. The rehabilitation work will simultaneously be started with construction work of the proposed road and it shall be ensured that the rehabilitation work is completed before completion of the construction of the proposed road.	Agreed, the area of 3.58 ha between proposed and existing alignment shall be properly fenced and planted with indigenous tree species in consultation with concerned DFO.
10	The User agency shall submit road side plantation the above-mentioned plantation schemes in consultation with the State Forest Department and the plantation shall be carried out by SFD at the cost of User Agency.	Agreed, Road side plantation shall be carried out.
11	The User Agency shall submit an undertaking that no muck shall be disposed off in forest land.	Agreed. Undertaking attach at Annex-III
12	The KML files of Diverted and CA areas shall be uploaded on the e. Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II Approval.	Pertaining to forest department.


PD

S. No	Conditions	Remarks
13	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	Agreed
14	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	Agreed
15	In case working permission is granted by the State Forest Department, a copy of the same shall be submitted with compliance report of Stage-I approval.	Agreed
B.		
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	Agreed
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 25.00 ha degraded-forest land at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species shall be avoided.	The Cost of Compensatory Afforestation, cost of NPV and other amount is 2,83,73,339 paid by NEFT UTR No LMS 4090050054347 to CAMPA account no 1507661153796668 dated 30.03.24 CAMPA Challan dated 21.03.2024 (Annex-I) and Account Statement dated 30.03.2024 is enclosed for ready reference (Annex-II)
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	Agreed. Undertaking attach at Annex-IV
4	The User Agency shall restrict felling of trees to the enumerated 775 numbers/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and the State Forest Department shall undertake the felling's.	Agreed.
5	Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost	Agreed
6	User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	Agreed
7	Speed regulating signages shall be erected all along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas	Agreed
8	Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Central Government.	Agreed
9	No labour camp shall be established on the forest land.	Agreed
10	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forests.	Agreed
11	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	Agreed


PD

S. No	Conditions	Remarks
12	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the project life.	Agreed
13	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	Agreed
14	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Arts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	Agreed
15	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of the Central Government	Agreed
16	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	Agreed

3. In view of the above, it is humbly requested to accord Working permission and grant Stage-II Clearance for taking up construction work and timely completion of aforesaid prestigious project of the Government of India on the said forest land falling under the Forest Divisions namely Harda, Betul & Narmadapuram which will greatly facilitate and assist the transportation and livelihood of people residing in nearby areas.

Encl.: As above.


 (Manish Kumar Meena)
 Project Director

Copy to:

- The Regional Officer, NHAI, Bhopal - for kind information please.
- DFO Harda - for kind information please.
- DFO Narmadapuram - for kind information please.
- DFO Betul (West) - for kind information please.

Full Title of the Project: Additional Land Required for 4 laning of Harda -Betul Section of National Highway (NH-47) from Temagav km 30+000 to Chicholi km 81+000 (length-51 km) under BHARATMALA Pariyojana Economic Corridor (Phase- I) in three districts of Harda, Hoshangabad and Betul in the State of Madhya Pradesh on EPC Mode

MUCK DISPOSAL CERTIFICATE

This is to certify that I, Project Director, NHAI PIU Harda, will ensure that no muck shall be disposed off in forest land.



Project Director
NHAI, PIU Harda
Madhya Pradesh



Nalini Gupta

Jed Prakash

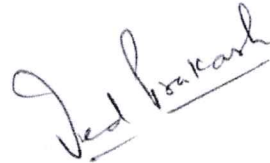
Full Title of the Project: Additional Land Required for 4 laning of Harda -Betul Section of National Highway (NH-47) from Temagav km 30+000 to Chicholi km 81+000 (length-51 km) under BHARATMALA Pariyojana Economic Corridor (Phase- I) in three districts of Harda, Hoshangabad and Betul in the State of Madhya Pradesh on EPC Mode.

UNDERTAKING FOR ADDITIONAL AMOUNT OF NPV

This is to certify that during Construction of "Additional Land Required for 4 laning of Harda -Betul Section of National Highway (NH-47) from Temagav km 30+000 to Chicholi km 81+000 (length-51 km) under BHARATMALA Pariyojana Economic Corridor (Phase- I) in three districts of Harda, Hoshangabad and Betul in the State of Madhya Pradesh on EPC Mode" additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency is agreed to pay any additional amount of NPV, if any



Project Director
NHAI, PIU Harda
Madhya Pradesh



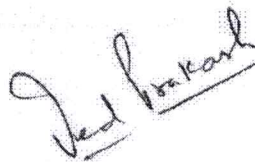
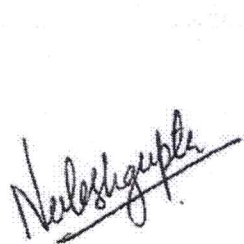
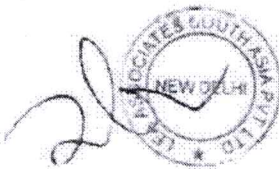
Full Title of the Project: Additional Land Required for 4 laning of Harda -Betul Section of National Highway (NH-47) from Temagav km 30+000 to Chicholi km 81+000 (length-51 km) under BHARATMALA Pariyojana Economic Corridor (Phase- I) in three districts of Harda, Hoshangabad and Betul in the State of Madhya Pradesh on EPC Mode.

UNDERTAKING FOR ADDITIONAL AMOUNT OF NPV

This is to certify that during Construction of "Additional Land Required for 4 laning of Harda -Betul Section of National Highway (NH-47) from Temagav km 30+000 to Chicholi km 81+000 (length-51 km) under BHARATMALA Pariyojana Economic Corridor (Phase- I) in three districts of Harda, Hoshangabad and Betul in the State of Madhya Pradesh on EPC Mode" additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency is agreed to pay any additional amount of NPV, if any



Project Director
NHAI, PIU Harda
Madhya Pradesh



FORM-I
(For linear projects)
Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector, Harda.

NO- FRA/2024/

Dated: 27/03/2024

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.061 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of PIU Harda, National Highway of Authority, Madhya Pradesh, Govt. of India for **Additional Land Required for 4 laning of Harda -Betul Section of National Highway (NH-47) from Temagav km 30+000 to Chicholi km 81+000 (length-51.000 km) under BHARATMALA Pariyojana Economic Corridor (Phase- I) in three districts of Harda, Hoshangabad and Betul in the State of Madhya Pradesh on EPC.** in district of Harda falls within jurisdiction of Village Usakalli in Rehatgaon tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.061 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to B annexure---
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, In vernacular language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Villages Usakalli in Rehatgaon tehsils.
- (d) Usakalli Village(s) is enclosed as annexure A to annexure B.
- (e) The discussion and decision on such proposals has been taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (f) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha's have given their consent to it;
- (g) the rights of Primitive Tribal Group and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA

Encls : As above.

Signature

(Full Name and Official seal of the District Collector)



FORM-I
(For linear projects)
Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector, Narmdapurm *****

No- FRA/2022/ 417

Dated: 12/01/2023


TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11- 9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.772 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of PIU Harda, National Highway of Authority, Madhya Pradesh, Govt. of India for Additional Land Required for 4 laning of Harda -Betul Section of National Highway (NH-47) from Temagav km 30+000 to Chicholi km 81+000 (length-51.000 km) under BHARATMALA Pariyojana Economic Corridor (Phase- I) in three districts of Harda, Narmdapurm and Betul in the State of Madhya Pradesh on Hybrid Annuity Mode. In district of Narmdapurm falls within jurisdiction of Village Dhekna in SeoniMalwatehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.772 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to B annexure—
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Village Dhekna in SeoniMalwatehsils.
- (d) Dhekna Village(s) is enclosed as annexure A to annexure B.
- (e) The discussion and decision on such proposals has been taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (f) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha's have given their consent to it;
- (g) the rights of Primitive Tribal Group and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA

Encls.As above.


Neeraj Kumar Singh
Collector
District Narmdapurm

FORM-II
(For projects other than linear projects)
Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector, Betul.

No.-FRA/2024-25/2787

Dated 25/06/2024

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ("FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that 6.566 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of **PROJECT DIRECTOR PIU Harda, National Highway of Authority, M.P. Govt. of India** of user agency for **Addition Land Required 4 laning of Harda-Betul Section of National Highway (NH-47) from TEMAGAV km 30+000 to Chicholi km 81+000 (length-51.000km) under BHARATMALA parijojana Economic corridor (phase-I) in three districts of Harda, Hoshangabad and Betul in the State of Madhya Pradesh on Hybrid Annuiyt Mode.** Betul District falls within jurisdiction of village **Khokraheda, Gawasen, Tanda, Kurasna, Ajai and Alampur** in Tehsil **Chicholi District Betul**

It is further certified that :

- A- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for **Gawsen Rang-Khokraheda** (CPN-4,8) 0.641, 0.43 total 1.071 hectare, **Gawasen** (CPN-9,10) 1.394, 0.744 total 2.138 hectare, **Tanda** (CPN-15,16) 0.872, 0.161 total 1.033 hectare, **Kurasna** (CPN-38,49) 1.029, 0.257 total 1.286 hectare, **Ajai** (CPN-369,1420) 0.628, 0.344 total 0.972 hectare and **Saoligarh Range Alampur** (CPN-1567) 0.066 hectare **Grntotal Area 6.566 hectare** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting's of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha (Mohalla Committey), Sub-Division Level Forest Rights Committee(s) **Betul** and the District Level Committee are enclosed as annexure A to B annexure C
- B- the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- C- the each of concerned Gram Sabha has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Khokraheda, Gawasen, Tanda, Kurasna, Ajai and Alampur** villages in Tehsil **Chicholi District Betul** is enclosed as annexure A to annexure B.
- D- Villages is enclosed as annexure A the discussion and decisions on such proposals has taken place only when there was a quoram of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- E- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- F- the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1){e} of the FRA.

Encl.: As above.

सहायक आयुक्त
जन जाति कार्य विभाग
बेतुल (म.प्र.)

Collector
DISTRICT BETUL

FORM-I
(For linear projects)
Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector, Harda.

NO- FRA/2024/

Dated: 27/03/2024

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.061** hectare of forest land proposed to be diverted in favour of PIU Harda, National Highway of Authority, Madhya Pradesh, Govt. of India for **Additional Land Required for 4 laning of Harda -Betul Section of National Highway (NH-47) from Temagav km 30+000 to Chicholi km 81+000 (length-51.000 km) under BHARATMALA Pariyojana Economic Corridor (Phase- I) in three districts of Harda, Hoshangabad and Betul in the State of Madhya Pradesh on EPC.** in district of Harda falls within jurisdiction of Village **Usakalli** in **Rehatgaon** tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.061** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to B annexure---
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Villages **Usakalli** in **Rehatgaon** tehsils.
- (d) **Usakalli** Village(s) is enclosed as annexure A to annexure B.
- (e) **The discussion and decision on such proposals has been taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.**
- (f) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the GramSabha's have given their consent to it;
- (g) the rights of Primitive Tribal Group and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1){e} of the FRA

Encls : As above.

Signature**(Full Name and Official seal of the District Collector)**

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

: This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

: This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.

: This icon shows that the challan has been generated.

: This icon shows that the payment yet to be made.

: This icon shows that the payment has been made.

Proposals received on or after 15th July 2014 All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Select State :

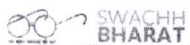
Select User Agency :

Payment Status : ☐ Paid ☐ Unpaid ☒ All

Enter value for Search :

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/MP/ROAD/153796/2022 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/ROAD/153796/2022) Additional Land Required for 4 Laning of Harda to Betul Section of National Highway (NH-47) from Temagav Km 30+000 to Chicholi Km 81+000 (Length-51 km) under BHARATMALA Pariyojna Economic Corridor (Phase-I) in three districts of Harda, Hoshangabad and Betul in the state of Madhya Pradesh on EPC Mode	ROAD1537962022668	05 Feb 2024	CA: 12109413/- Addl CA 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA 0/- Beat : NPV: 14571709/- Gaurd 1692217/- Chowki etc : Total : 28373339/-		Fund Demand Verified by : 20 Mar 2024 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 21 Mar 2024 Transaction Date : 30 Mar 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/190320241739591891_FPMROAD1537962022_User_Fund_De) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD1537962022668)



(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



Power To Empower

(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)



Open Government Data (OGD) Platform India

MeitY

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilstatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in



FCA Projects, Diverted Land, CA Land Management

Home FCA-1980 Projects Diverted Lands CA Lands Reports

INFORMATION

SUCCESS: The FCA project has been Registered sucessfully. You can now edit the project details and lock for ID:54097

**Additional Land Required
for 4 Laning of Harda to
Betul Section of National
Highway (NH-47)from
Temagav Km 30+000 to
Chicholi Km
81+000(Length- 51 km)
under BHARATMALA
Pariyojna Economic
Corridor (Phase-I) in three
districts of Harda,
Hoshangabad and Betul in
the state of Madhya
Pradesh on EPC Mode**

Project Name : Year : **2024**

- To Register a new FCA Project, please click here [Register a New FCA Project](#)
- To Edit details of Existing FCA Project, Please click here [Edit the Existing FCA Project Details](#)
- To Lock the Details of FCA Project, Please click here [Lock FCA Projects](#)
- [Add CA Land / Site Details to the Project](#) Please click here to add the CA Site/Land Details to the Project.